



एक नजर
महेन्द्रनाथ पाण्डेय
बनाए गए भाजपा
यूपी चुनाव अधिकारी



लखनऊ (आभा) प्रदेश भाजपा और जिलों में नए अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा

जम्मू-कश्मीर फिर बनेगा पूर्ण राज्य, उमर अब्दुल्ला
कैबिनेट के प्रस्ताव को एल.जी. ने दिया मंजूरी

श्रीनगर (आभा) गुजरात को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया। जम्मू-कश्मीर के राज्य के बहाल करने



का मंजूरी दे दी है जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। अतिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। गुजरात को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया, जम्मू-कश्मीर के राज्य के बहाल करने

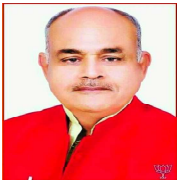
दीपावली से पहले सड़कों को गड़्ढा मुक्त करने का निर्देश

लखनऊ (आभा) प्रदेश सरकार ने शहरों में सड़कों को दीपावली से पहले अनिवार्य रूप से ठीक करने के निर्देश दिए हैं। विकास प्राधिकरण



का निर्देश दिया गया है कि सड़कों को विशेष अभियान चलाकर गड़्ढा मुक्त किया जाए और जिनके टैंडर हो चुके हैं उनके काम पूरे कराए जाएं। प्रमुख सचिव आवास पी

राजेन्द्रनाथ तिवारी को भाजपा प्रदेश
चुनाव अधिकारी बनाये जाने पर प्रसन्नता



भारतीय बस्ती संवाददाता-बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी संसाद दा

के अनुरूप भाजपा के पदाधिकारियों के चयन में सह चुनाव अधिकारी का दायित्व निभायेगा। भाजपा के प्रदेश कार्य

सम्पूर्ण समाधान दिवस में 9 मामले निस्तारित

भारतीय बस्ती संवाददाता-बस्ती। सम्पूर्ण समाधान दिवस रूधौली तहसील समागार में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। प्रतीक



राज्य के 30, विकास के 7, विद्युत के 4, समाज कल्याण के 03, पुलिस, लीड बस व पूर्ति के 2-2 तथा कृषि व नगरपालिका-1 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में

बैंक में सैधमारी
के मामले में
मुकदमा दर्ज

शुआबा की देर रात कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महारणजपुर कस्बे में स्थित बडीदा वृषी बैंक में एक सदिर-

अश्लील वीडियो मामले
में मुकदमा दर्ज

श्रीनगर (आभा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रियंका त्रिपाठी को पी.एच.डी. उपाधि



भारतीय बस्ती संवाददाता-बस्ती। शहर से सटे लवनापुर निवासी केशरी नारायण त्रिपाठी की

महन्थ यति नरसिंहानन्द सरस्वती के
विरुद्ध कार्यवाही की मांग: सौंपा ज्ञापन

लखनऊ (आभा) उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्रियों

जैसे ही ग्रामीणों को हुई उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मोंके पर पहुंची पुलिस को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना का

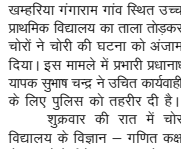
उप चुनाव में जीत के लिये मुख्यमंत्री योगी ने सौंपी जिम्मेदारी

लखनऊ (आभा) उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्रियों

विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी

हरैया थाना क्षेत्र के खन्हरिया गंगाराम गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में प्रभारी प्रान्धन

विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी



हरैया थाना क्षेत्र के खन्हरिया गंगाराम गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में प्रभारी प्रान्धन

उप चुनाव में जीत के लिये मुख्यमंत्री योगी ने सौंपी जिम्मेदारी

लखनऊ (आभा) उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्रियों



"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निष्ठाक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 20 अक्टूबर 2024 रविवार

## सम्पादकीय

### नायब सिंह सैनी की दूसरी पारी

भले ही यह अप्रत्याशित हो, लेकिन यह एक टकसाली हकीकत है कि हरियाणा में भाजपा को तीसरे कार्यकाल के लिये स्पष्ट जनादेश मिला है। हो सकता है पार्टी यह कहे कि यह निर्णायक जनादेश भाजपा के शासन मॉडल के प्रति विश्वास मत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, लेकिन इसके विवाजुद ज़रूरत इस बात की है कि उन मुद्दों पर मंथन किया जाए जिनको लेकर चुनाव के दौरान जनता में असहजता थी। निस्संदेह, नायब सिंह सैनी, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छाया में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ने पिछली बार से अधिक सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनायी है। मगर जिस चीज से नायब सिंह सैनी को सावधान रहने की ज़रूरत है, वह है अति-आत्मविश्वास। हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अति-आत्मविश्वास की कीमत चुकाई है। निस्संदेह, सैनी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के पास हरियाणा में आधारभूत बसने से जनाकाक्षाओं को हकीकत में बदलने का सुनहरा मौका है। उन्हें पूर्ण बहुमत वाली सरकार के रूप में जनाकाक्षाओं को पूर्ण करने के लिये कृ तसंकल्प होने की ज़रूरत है। दरअसल, चुनावी राजनीति में जनता के दरबार में उछले विपक्षी नेताओं के आरोप कई बार सत्तापक्ष को आत्मविश्लेषण का मौका भी देते हैं। चुनावी माहौल में जहां विपक्षी दल सत्ता पक्ष की रीतियों-नीतियों को लेकर मुखर होते हैं, वहीं ऐसे मोके पर जनता की अभिव्यक्ति का भी अहसास होता है। भाजपा जैसे कुशल संगठन वाली कैंडिड आधुनिक पार्टी से उम्मीद की जाती है कि जिस तरह उसने चुनावों में माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसी तरह उसकी सरकार से भी उम्मीद की जाती है कि वह सहस्रधाओं को भी बेहद करीब से सूक्ष्म स्तर पर महसूस करेगी। बहरहाल, भाजपा की इस जीत ने एक संदेश यह भी दिया है कि महज सत्ताधिरोंभी रुझान ही चुनाव परिणामों की दिशा-दशा तय नहीं करते। बदलाव की आकांक्षा को सुशासन व बेहतर प्रबंधन के मुद्दे भी गहरे तन प्रभावित करते हैं।

निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की दूसरी पारी में कार्यभार संभालने वाले नायब सिंह सैनी की सरकार पर जनाकाक्षाओं का भारी दबाव होगा। उनका प्राथमिक उद्देश्य जनता से किये गए वायदों और उनके क्रियान्वयन होगा, जिससे जनता सुशासन की उपलब्धि महसूस कर सके। निश्चित रूप से किसी योजना की सांख्यिक इस बात पर निर्भर करती है कि जनता उससे किस हद तक लाभान्वित महसूस करती है। कई बार व्यवस्था की विसंगति इस मार्ग में बाधक बन जाती हैं। इसके लिये आयाचना व क्रियान्वयन में साम्य जरूरी हो जाता है। निस्संदेह, पिछले साल में जब सैनी ने अपने गुरु मनोहर लाल खड्कर की छत्रछाया में सरकार का दायित्व हासिल किया था तो उन्हें राजनीतिक हलकों में गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में न केवल खुद को सावित किया बल्कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। निस्संदेह, हरियाणा के इस नये जनादेश के दूरगामी परिणाम होंगे। इतना ही नहीं इस जीत ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में भी एक नया उत्साह भर दिया। यह उत्साह महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव अभियान में भी नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इन चुनावों ने मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी का राजनीतिक कद बढ़ाया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी उन्हें सकारात्मक प्रतीसाद व संबल मिला है। वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ गई हैं। उन्हें क्षेत्र व जाति की सीमाओं से परे 'सबका साथ, सबका विकास' का लक्ष्य हासिल करना है। उनके लिये यह सुखद है कि जहां राज्य में उन्हें पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने से पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, वहीं केंद्र से भी उन्हें भरपूर समर्थन मिला रहा है। निस्संदेह, उन्हें 'डबल इंजन की सरकार' के मुहाने पर को साकार करने का अवसर मिला है। जखरत इस बात की शिंशे वे पूर्व सरकार के मुखिया की छाया से निकलकर शासन की नई सर्व स्वीकार्य दिशा तय करेंगे। वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहमत नजर आएँ, जिससे राज्य में सरकार की स्वीकार्यता बढ़ सके। जिसमें पार्टी के वरिष्ठ विधायकों का अनुभव व कनिष्ठ विधायकों की ऊर्जा मददगार होगी।

# लोकतंत्र की डगर पर एक राष्ट्र, एक चुनाव



—शशि थरूर—

भारतीय लोकतंत्र की गरिमा बचाने वाला एक अनुग्रह है— हालांकि कुछ लोगों के लिए यह भारत की स्वयंसे अधिक परेशान करने वाली खबरों के एक होंग। कि व्यवहारिक रूप से यहां सदा कोई न कोई चुनाव चलता रहता है। इस लिए, पिछले आम चुनाव की गूज जैसे ही खत्म हुई दु जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद पर तो बना रहा, लेकिन बहुमत के बिना और गठबंधन सरकार के नेतृत्व के साथ जल्द ही हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में क्रियान्वयन चुनाव के लिए मतदान हुआ। जिसके पिछले सप्ताह घोषित परिणामों ने राजनेताओं और चुनाव विश्लेषकों, दोनों को चौंका दिया।



हरियाणा में मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अल्पशासित जीत हासिल की, जहां पर उसकी हार की उम्मीद बताई जा रही थी। वहीं जम्मू-कश्मीर में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने अपने क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल कॉन्ग्रेस के साथ मिलकर जीत पाई, जबकि वहां पर चुनावों में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलने के कारण त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। जून के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव पड़ितों के कयास गलत निकले थे दु उन्होंने भाजपा की तगड़ी जीत का अनुमान लगाया था दु निश्चित तौर से भारत के मतदाता का अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता।

अपेक्षाओं को घटा बताने के और अधिक मंके भारतीय मतदाताओं को शीघ्र ही मिलने जा रहे हैं। साल पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने हाल ही में इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए एक वृहद रिपोर्ट तैयार की, जिससे पीएम मोदी ने एक राष्ट्र, एक चुनाव का नाम दिया है।

उनावों की बारम्बारता वास्तव में किसी राष्ट्रीय सरकार के लिए एक स्थानीय की मसलन, जहां राज्य व स्थानीय चुनावों में अलग-अलग मुद्दे प्रभावी होते हैं और अक्सर इन्हें राष्ट्रीय सरकार पर एक प्रकार के जगमत संग्रह के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर, स्वतंत्र चुनाव आयोग की आदर्श आधार सहितता के कारण चुनाव के दौरान शासन व्यवस्था ठप हो जाती है, ताकि कार्यकारी सरकार ऐसी भीतिगण घोषणाएं न करने पाए, जिससे कि मतदाता उनके बचने में मतदान करने के लिए प्रभावित हो। इसके अलावा, राष्ट्रीय नेता चुनाव वाले राज्यों में प्रचार करने में व्यस्त

हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना राजनीतिक इतिहास होता है और अक्सर, उनकी अपनी उनके गृह भी। पीएम मोदी और उनके गृह भी अमित शाह और उनके स्वर्ण कार्यकाल के दौरान अतीत चुनावी अभियान में व्यस्त रहे, जिससे कि उनके अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए बहुत कम समय बचा। प्रधानमंत्री मोदी की दलील है कि बार-बार चुनाव करने से पैसा और संपत्ति दोनों बर्बाद होते हैं। हो सकता है उन्हें यह विचार भी आया होगा कि एक साथ चुनाव करवाने पर राष्ट्रीय पार्टियों और मुद्दे का फायदा राज्य चुनावों में मिल सकता है, ताकि राष्ट्र व्यापी चुनाव प्रचार में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थकों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना कम हो जाए।

विषय इस प्रस्तावित सुधार को खारिज करता है, यह इंगित करते हुए कि सभी चुनाव एक साथ करवाने के लोकाव्ययों को लंबे समय से विवादायक है कि राष्ट्रपति प्रणाली तानाशाही को बढ़ावा देगी, और इसी लिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन संसदीय प्रणाली ने अपनी किम की निरकुलता बनाई है, क्योंकि अति आत्मविश्वासी कार्यपालिका ने विधायी बहुमत को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति प्रणाली में, कार्यपालिका एक स्वतंत्र विधायिक केंद्र के प्रति जवाबदेह होगी, यह विधायिका को नोटिस बोर्ड और खर की मुहर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसा कि भाजपा एक दशक से कर रही है।

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का तकनीकी युग

### —सुश्री शोभा करंदला—

वर्तमान समय में, विश्व तीव्र गति से एक ऐसे तकनीकी भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक आर्थिक का केंद्र बिंदु बन गया है। हमारे मानवीय प्रणामी नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत का लक्ष्य हमारे युवाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आने वाले समुदायों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, पूर्वसैनिकों और आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों जैसे पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से उद्यमिता को एक व्यवहार्य करियर मार्ग के रूप में लेने के लिए प्रेरित करना है। उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम का विजन केवल करोड़ों के सृजन तक ही नहीं, बल्कि इससे आगे तक जाता है। यह बेरोजगारी को संबोधित करने के साथ-साथ जातीय विकास को बढ़ाने और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।



इसके साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर में ऋण गारंटी योजना की घोषणा से प्रेरणता की लहर है, जो मशीनों के लिए 100 करोड़ रुपए तक के जमानत-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है। जमानत-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है। इस वष से केंद्रीय बजट में संघट की अवधि के दौरान ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को शुरू किया गया है जो सरकार-गारंटीड निधि द्वारा समर्थित है और ये व्यवसायों को गैर-निष्ठावित्त परिसंपत्ति बनने से रोकने में मदद करता है और समग्र आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है।

‘रक्षण’ श्रेणी को लक्ष्य को लक्ष्य के लिए मुद्रा ऋण को दोगुना करके 20 लाख रुपए करके एक कार्की बड़ा प्रोत्साहन है, जो व्यवसायों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने और रोजगार सृजन को बढ़ा देने में सक्षम बनाता है। कम रकमों पर सीमा और विस्तारित पात्रता के साथ व्यापार प्राय चूट

## स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते कूड़े के खिलवाड़

### —ज्ञानेन्द्र रावत—

दिल्ली में कूड़े के पहाड़ गंभीर समस्या बन चुके हैं, और इस पर प्रणामी कार्यलय में भी चिंता जलाई है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गठित विशेष कार्यलय की बैठक में कचरे के निपटान में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर कचरा निपटान के लिए मौजूदा कानूनों के सख्त अनुपालन और कचरे से बिजली बनाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही, सख्तों और निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण के उपायों की भी प्राथमिकता देने की बात की गई।



वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में वर्षों से जमा कूड़े के ढेरों को समाप्त करना था, जो अब पहाड़ की शकल ले चुके हैं। यह मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू हुआ, और एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1 अक्टूबर 2021 को आया जब एनएचएम-20 की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया, और यह सुनिश्चित किया गया कि मिथिल में ऐसी समस्याएं न उमरें।

केंद्र सरकार ने कूड़े के ढेरों को समाप्त करने के लिए 3000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है, जिसमें राज्यों से सौभाग्य गारंटी की अंशे की गई थी। हालांकि, राजनीतिक दायित्व के चलते इन कूड़े के पहाड़ों का निवारण अब तक नहीं हो सका है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में केवल 15 फीसदी कूड़े के पहाड़ को हटाया है, जिसकी आंशिक हारा और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भी पुष्टि की गई है। यह स्थिति समस्या के समाधान में अतिच्छा और समन्वय की कमी को दर्शाती है।





